www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY/169/2015-2017

प्रखर...मुखर...स्वर

विदर्भ की बात SUNDAY

● वर्ष 17 ● अंक 160 नागपुर, रविवार, 7 मई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

अजलन शाह हॉकी: भारत ने न्यूजीलैंड को 4-0 से रौंदकर जीता ब्रॉन्ज मेडल

मलेशिया

पिछली बार की उपविजेता भारतीय टीम को 26वें अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा है। शनिवार को कांस्य पदक मुकाबले में उसने न्यूजीलैंड को 4-0 से रौंदकर अपना अभियान समाप्त किया। भारत शुक्रवार को मलेशिया से 0-1 से हारकर खिताबी दौड़ से बाहर हो गया था। न्यूजीलैंड को चौथा स्थान हासिल हुआ, जबकि मेजबान मलेशिया की टीम जापान को 3-1 से हरा पांचवां स्थान पर रही। रुपिंदर पाल सिंह ने भारत को 2-0 से शुरुआती बढ़त दिलाई। उन्होंने 17वें और 27वें मिनट में गोल दागे। इसके बाद बर्थडे ब्वॉय एसवी सुनील ने 48वें मिनट में बढ़त को 3-0 कर दी। जबकि 60वें मिनट में तलविंदर सिंह ने भारत को 4-0 से आगे कर दिया, जो निर्णायक साबित हुआ। (■पृष्ठ 3 भी देखें)

26 सालों बाद असम के इन क्षेत्रों से हट सकता है अफस्पा

गुवाहाटी

आर्म्ड फोर्स (स्पेशल पावर) एक्ट यानि अफस्पा हमेशा से ही विवादों में रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में असम के कुछ क्षेत्रों से इस विवादित एक्ट को हटा लिया जाए। असम की सरकार केंद्र की सिफारिशों से पहले राज्य के कुछ इलाकों से अफस्पा हटाने पर विचार कर सकती है।

अगर असम के कुछ इलाकों से अफस्पा हटाया जाता है तो इसका प्रभाव जम्मू-कश्मीर और मणिपुर में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल, जहां अफस्पा केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। असम में अफस्पा को लगे लगभग 26 साल बीत चुके हैं। असम को अशांत इलाका कहते हुए केंद्र सरकार ने 27 नवंबर 1990 को इस अधिनियम को लागू किया था। केंद्र ने उल्फा के नेतृत्व में आतंकवाद पर काबू पाने के लिए यह फैसला लिया था।

बता दें कि अफस्पा अधिनियम देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सशस्त्र बलों को कुछ खास शक्तियां प्रदान करता है। राज्य के एडीजी (स्पेशल ब्रांच) पल्लाब भट्टाचार्य ने कहा कि अफस्पा पिछले 26 साल से राज्य में लागू है। गृह मंत्रालय के साथ हुई पिछली बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था। कई जगहों से इस अधिनियम को हटाने की मांग भी की जा रही है। अधिनियम किन इलाकों से हटाया जाना चाहिए यह फैसला चर्चा के बाद लिया जाएगा। इस समय राज्य में बड़ी संख्या में सेना के जवान तैनात हैं। अभी यह कानून पूरे राज्य में लागू है।

चीन से आए कंटेनर से गैस हुई लीक, 300 छात्राएं बीमार, 10 एम्स में भर्ती

नई दिल्ली

राजधानी के तुगलकाबाद कंटेनर डिपो में एक कंटेनर में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। गैस रिसाव के चलते डिपो के पास नजदीक के रानी झांसी सर्वोदय विद्यालय की बीमार 300 छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आस-पास के लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत की है।

बताया जा रहा है कि कंटेनर में रखे गए इस रसायन को चीन से आयात किया गया था और इसे हरियाणा के सोनीपत ले जाना था। मौके पर एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस और की टीम मौजूद है। दिल्ली फायर ब्रिगेड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब सात बजकर 35 मिनट पर गैस रिसाव से संबंधित खबर मिली थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। इस मामले में 10 से अधिक मरीज के एम्स के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे हैं। दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सीसोदिया ने कहा कि गैस रिसाव की वजह से 110 छात्राओं ने आंखों में जलन की शिकायत की थी। उन्हें पास के तीन बड़े अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। मेरी छात्राओं और डॉक्टर्स से बात हुई है, सबकी हालात सामान्य है ।

कंटेनर डिपो से गैस लीक होने के मामले की जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा है, वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी अस्पतालों को गैस रिसाव पीड़ितों की मदद करने को तैयार रहने का निर्देश दिया है। तुगलकाबाद के जिस कंटेनर डिपो में गैस का रिसाव हुआ है उसका शहर से बाहर करने की लम्बे समय से मांग की जा रही है। डिपो के आसपास रानी झांसी स्कूल के अलावा 6 प्राथमिक विद्यालय हैं। डिपो के अंदर वीपी कैम्प में 15 हज़ार लोग रहते हैं। प्राप्त जानकारी की अनुसार क्लोरोमिथिने पैरेडिने गैस का लंबे समय तक रिसाव आंखों में चुभन और जलन की वजह बन सकता है। इस बावत पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था के डॉ. पीयूष माहप-त्रा ने बताया कि गैस के संपर्क में आने से सांस सम्बन्धी परेशानी भी हो सकती है। हालांकि रिसाव के असर का पता अभी नहीं लगेगा, इसलिए बच्चों का लम्बे समय तक स्वास्थय परीक्षण किया जायेगा। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

भारतीय मिशन प्रमुखों के साथ पीएम की बैठक में चीन-पाक के साथ संबंधों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विदेश नीति के प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित भारतीय मिशन प्रमुखों की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में बड़ी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों के अलावा पाकिस्तान एवं चीन के साथ संबंधों में आया तनाव भी चर्चा का विषय रहा।

बैठक में करीब 120 राजदूतों ने लिया हिस्सा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने प्रधानमंत्री के संबोधन की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मिशन प्रमुखों के आठवें सम्मेलन को संबोधित किया।

इस सम्मेलन में दुनिया भर में तैनात लगभग 120 राजदूतों ने हिस्सा लिया। बड़े ताकतवर देशों के साथ भारत के संबंधों के अलावा पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों में आया तनाव विदेशी नीति के उन प्रमुख मुद्दों में शामिल है, जिनपर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की जा रही है।

चार दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन सुषमा स्वराज ने किया

शुक्रवार को शुरू हुए इस चार दिवसीय सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था। इस सम्मेलन में वैश्विक तौर पर हो रहे बड़े बदलावों पर भी चर्चा की संभावना है। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा होनी है कि भारत को इन बदलावों से निपटने के लिए किस तरह अपनी नीति में बदलाव लाने चाहिए। राजदूतों ने उन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर प्रेजेंटेशन दिया, ■ शेष पृष्ठ 2 पर

एलओसी पर बोफोर्स तोपें तैनात, पाक ने बढ़ाई जवानों की संख्या

जम्मू

दो भारतीय जवानों के सिर कलम करने की घटना के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। जम्मू-कश्मीर में राजौरी से लेकर पुंछ तक नियंत्रण रेखा पर सेना ने बोफोर्स तोपें तैनात कर दी हैं। जगह-जगह छोटी तोपें भी लगाई गई हैं। बोफोर्स तोपों की जगह हर दो-तीन घंटे बाद बदली जा रही है, ताकि दुश्मन को पता न चल सके। उधर, सीमा पार पाक सेना ने भी जवानों की संख्या बढ़ा दी है। वहां भी सीमा पर तोपें लगाई जा रही हैं।

तमिलनाडु के सरकारी डॉक्टरों का आंदोलन जारी, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

चेन्नई

तमिलनाडु में सरकारी डॉक्टरों के हड़ताल से ओपीडी सेवाएं चरमरा गई है। राज्य में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अपने लिए 50 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर सरकारी डॉक्टर लगातार कई दिनों से अपने काम का बहिष्कार कर रहे हैं। विभिन्न संगठनों से संबद्ध चिकित्सक दो मई से आंदोलनरत हैं और राज्यभर भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वे पहले से तय ऑपरेशनों में हिस्सा नहीं ले रहे । हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि वे आपातकालीन मामलों को देख रहे हैं। संगठनों ने आठ मई को एक दिन के संकेतिक हड़ताल की घोषणा की है जो कि पीजी पाठ्यक्रमों में सेवा में शामिल डॉक्टरों को दिए गए आरक्षण को खत्म करने के विरोध में है।

विदेशी मरीजों के उपचार की गाइड लाइन बनाएगी महाराष्ट्र सरकार

मुंबई

सूबे के अस्पतालों में विदेशी मरीजों के उपचार को लेकर महाराष्ट्र सरकार जल्द ही गाइड लाइन बनाएगी। दुनिया की सबसे वजनी महिला रहीं मिस्र की इमान अहमद के इलाज को लेकर विवाद होने के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। इमान की बहन शाइमा ने सैफी अस्पताल के सर्जन डॉक्टर लकड़वाला पर लापरवाही का आरोप लगाया था।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने कहा, इमान का वजन सर्जरी के बाद जिस तरह से कम हुआ वह गर्व की बात है। यह महाराष्ट्र में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि, इस मामले से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैं समझता हूं कि चीजों को नकारात्मक होने से बचाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बाबत अधिकारियों को नोट तैयार करने को कहा है।

एसओपी में दस्तावेज, मरीज के परिजनों से सूचनाएं साझा करने और संबंधित देश के दूतावास को जानकारी देने में सावधानी बरतने को लेकर दिशा-निर्देश होंगे। मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देने और इलाज के लिए दूसरे देश में स्थानांतरित करने को लेकर भी निर्देश दिए जाएंगे।

498 किलोग्राम वजनी इमान 11 फरवरी को मुंबई के सैफी अस्पताल में भर्ती हुई थीं। इलाज के लिए गुरुवार को अबुधाबी भेजे जाने से पहले उनका वजन 170 किलो तक पहुंच गया था।

बद्रीनाथ मंदिर के खुले कपाट, राष्ट्रपति ने की पूजा-अर्चना

बद्रीनाथ

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट पुन: खुलने पर शनिवार सवेरे यहां पूजा की। सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नम्बूरी ने वैदिक मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच तड़के सवा चार बजे मंदिर के कपाट खोले।

राष्ट्रपति ने मंदिर में दो घंटे बिताए

राष्ट्रपति मुखर्जी समुद्र तट से 10,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित सातवीं सदी के इस तीर्थस्थल पर पूजा करने के लिए सुबह आठ बजकर 25 मिनट पर यहां पहुंचे। मुखर्जी ने उत्तराखंड के राज्यपाल कृष्णकांत पॉल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ मंदिर में दो घंटे बिताए।

इसके बाद वह वहां से पूर्वाह्न 10 बजकर 25 मिनट पर जॉलीग्रांट हवाईअड्डे के लिए रवाना हुए, जहां से उन्हें दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी।

ज्ञातव्य है कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट पुन: खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की पूरी तरह से शुरुआत हो जाती है क्योंकि तीर्थयात्रा के अन्य तीन धाम पहले की खुल जाते हैं। इस यात्रा का अनेक श्रध्दालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। चारधाम यात्रा के एक अन्य बड़े मंदिर केदारनाथ के कपाट तीन मई को फिर से खुले थे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा की थी।

गृहमंत्रालय की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी

कोलकाता

वामपंथी उग्रवाद से निपटने की रणनीति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सोमवार को बुलाए गए मुख्यमंत्रियों की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के 25 जवानों की हाल में हुई हत्या के बाद आयोजित मीटिंग में गृहसचिव मलय डे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।

राज्य प्रशासन के अंदरुनी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री इस मीटिंग में नहीं शामिल होगी क्योंकि पहले से ही व्यस्त होंगी। पिछले माह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के बैठक में भी बनर्जी नहीं शामिल हुईं थीं। उन्होंने वित्तमंत्री अमित मित्रा को बैठक के लिए भेजा था, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री का निर्णय था कि राज्य का प्रतिनिधित्व केवल मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ही कर सकते हैं और इसलिए मित्रा बैठक में शामिल नहीं हो सके। राजनीतिक समीक्षकों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए सभी बैठकों से गायब होकर बनर्जी 2019 में एनडीए के विरोध में खड़े होने की तैयारी में जुटी हैं। हालांकि वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि पहली बार ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद बंगाल में एक एनकाउंटर में किशनजी की हत्या के साथ माओवादियों से खतरा का अंत 2011 में हो गया था। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री चाहती हैं कि गृह सचिव माओवादी खतरे को हटाने में बनर्जी सरकार की सफलताओं को पेश करें। बनर्जी कैबिनेट के मंत्री ने बताया, ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद जंगलमहल में माओवादी द्वारा एक भी इंसान को नहीं मारा गया।

आम आदमी बनकर चीफ जस्टिस ने पकड़ा बिल्डर का झूठ

मुंबई

दक्षिण मुंबई में जमीन का एक बड़ा हिस्सा फिर से आम जनता के लिए खुल जाएगा। यह फैसला तब लिया गया जब बॉम्बे हाईकोर्ट की मुख्य न्यायधीश मंजुला चेल्लुर आम नागरिक बनकर औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गईं। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने पाया कि डिवेलपर पर गैरकानूनी रूप से जमीन पर कब्जा करने का आरोप सही है।

जस्टिस चेल्लुर जब एक आम नागरिक की तरह मुंबई के कफ परेड स्थित डीएसके दुर्गामाता लग्जूरिअस अपार्टमेंट के पार्क में जाने लगीं तो उन्हें वहां मौजूद एक सिक्यॉरिटी गार्ड ने रोक लिया। न्यायमूर्ति चेलूर ने इसके बाद परिसर को सार्वजनिक खुली जगह के रूप में बहाल करने और बीएमसी द्वारा परिसर की सुरक्षा को वापस लिए

जाने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई जून में होगी।

मामला प्रकाश पेथे मार्ग पर 16 हजार स्केयर फीट प्लॉट का है, जहां डीएसके डिवेलपर्स को जमीन के 33 प्रतिशत हिस्से पर जिम्नाजियम बनाने की इजाजत दी गई। बाकी के बचे 67 प्रतिशत हिस्से (11 हजार स्केयर फीट जमीन) को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए छोड़ा गया था।

इस मामले में एक्टिविस्ट संजय कोकाटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बिल्डर ने क्लब हाउस बनाने के लिए जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, उसमें से छोटी सी जमीन ही पब्लिक के लिए छोड़ी गई है। याचिका में कहा गया है कि बीएमसी के साथ किए गए एग्रीमेंट की कई शर्तें बिल्डर ने तोड़ी हैं।

याचिका दायर करने के 8 महीने बाद हाईकोर्ट ने मार्च में टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को प्लॉट का निरीक्षण करने के लिए कहा। शुक्रवार को टीम ने मामले की रिपोर्ट सब्मिट की, जिसमें जस्टिस चेल्लुर ने खुद पाया कि जमीन के इस टुकड़े का इस्तेमाल पब्लिक को नहीं करने दिया जा रह है।

हाईकोर्ट ने तुरंत जमीन को पब्लिक स्पेस के तौर पर डिवेलप करने के लिए कहा।

जहां डीएसके डिवेलपर्स ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, वहीं इन्सपेक्शन कमिटी ने कहा कि मौके पर उन्हें आम जनता के लिए कोई जगह नजर नहीं आई। अपनी सात पेज की रिपोर्ट में कमिटी ने कहा, हमें वहां बच्चों के खेलने के लिए कोई इंतजाम नजर नहीं आए, यहां तक कि किसी के बैठने के लिए कोई बेंच तक नहीं थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके पर ऐसा कोई बोर्ड भी नहीं लगा था, जिस पर लिखा हो कि यह जमीन आम जनता के इस्तेमाल के लिए है, जबकि एंट्री के वक्त ने यह कहकर जाने से रोक दिया कि यह जगह प्रतिबंधित है। रिपोर्ट में कहा गया, हमें गेट पर एंट्री करने से रोका गया,। जब हमने अपनी पहचान बताई उसके बाद ही हमें अंदर जाने दिया गया।

याचिकाकर्ता कोकाटे के वकील युसुफ इकबाल ने कहा कि किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के निजी इस्तेमाल का यह बेतहरीन उदाहरण है। जब चीफ जस्टिस अपनी पहचान छुपाकर प्रॉपर्टी पर जाने लगी तो उन्हें भी वहां जाने से रोक दिया गया। कोर्ट जून में मामले को लेकर अंतिम फैसला सुनाएगी।

गुजरात की नई चुनावी टीम के साथ राहुल ने की बैठक

नई दिल्ली

गुजरात में करीब दो दशक सत्ता से बाहर कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सब कुछ झोंकने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी हाईकमान खुद गुजरात की चुनावी तैयारियों के साथ रणनीति पर निगाह रख रहा है। इसलिए गुजरात की कांग्रेस की नई केन्द्रीय चुनावी टीम जैसे ही जमीनी हाल लेकर लौटी वैसे ही राहुल गांधी ने शनिवार को उसके साथ बैठक की।

गुजरात की केन्द्रीय चुनावी टीम के साथ बैठक की जानकारी तो कांग्रेस की ओर से खुद ही दी गई मगर इसमें हुई चर्चा का ब्यौरा नहीं दिया गया मगर पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने नई टीम के साथ उनके दौरे की पहली फीडबैक ली।

इसमें पार्टी संगठन की जमीनी हालत, मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नेताओं के प्रभाव और उनके बीच आपसी समन्वय से लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ मुद्दों की फेहरिस्त पर खास चर्चा हुई। इस बैठक में गुजरात के नए प्रभारी महासचिव अशोक गहलोत के साथ सचिव जीतू पटवारी, राजीव साटव, हर्षवर्धन सापकल और वर्षा गायकवाड़ मौजूद थीं।

गौरतलब है कि गुजरात चुनाव की अहमियत को देखते हुए करीब दस दिन पहले कांग्रेस नेतृत्व ने गुरुदास कामथ की जगह अशोक गहलोत को राज्य का नया प्रभारी महासचिव नियुक्त किया था और उनके साथ चार सचिवों की टीम भी सहयोग के लिए लगाई गई।

चुनावी जिम्मा मिलने के बाद इस टीम ने गुजरात का दौरा कर शनिवार को राहुल के साथ पहली बैठक में सूबे में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की शुरुआती हालत से रूबरू कराया।